www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 341 | जौनपुर, शनिवार, 01 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से अधिक की कमी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने शनिवार को प्रमुख शहरों में 19–किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से अधिक की कटौती की। इससे रेस्तरां, होटल और खाना पकाने के लिए इस ईंधन पर निर्भर अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों को राहत मिली है। दिल्ली और कोलकाता में 19–किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से अधिक की कमी की गई है। 1 अगस्त से लागू हुई इस नई दर के तहत, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए कम हो गई है। कीमत में कटौती के बाद आज से दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,728 रुपए हो गई है। वहीं, कोलकाता में सिलेंडर की नई कीमत 2,872.50 रुपए है। हालांकि, यह कटौती सिर्फ कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल करने वालों के लिए है। 14.2–किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले, 1 जुलाई को कंपनियों ने प्रमुख शहरों में 19–किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 183.5 रुपए तक की कटौती की थी। कीमतों में यह कटौती ऐसे समय में की गई, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई थी।फिलहाल, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती के लिए कई लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है।

राहुल गांधी भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत दिखा रहे: शहजाद पूनावाला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने शनिवार को निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा साधु के वेश में चंदा मांगने का विरोध करते हुए गंभीर आरोप लगाया है। भारत राष्ट्रीय समाचार पूनावाला ने संसद परिसर में पप्पू यादव के प्रदर्शन और राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा चंदा देने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ष्राहुल गांधी बेशर्मी से हिंदुओं से नफरत करते हैं। एक पार्टी के प्रति अपनी नफरत में वे भारत और हिंदुओं के प्रति भी नफरत दिखाते हैं शहजाद पूनावाला ने वीडियो में कहा, ष्किसी मुद्दे को उठाने और पूरे हिंदू समाज को निशाना बनाने के लिए उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने में फर्क है। संसद परिसर के अंदर जो हुआ दृ जब पप्पू यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, वह बेवकूफी भरा और शर्मनाक था। पप्पू यादव साधु के वेश में आए और राम मंदिर चंदा घोटाले के मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। यह मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा है और इसे उठाया जाना चाहिए। लेकिन चोरी के आरोपी, जो अब जेल में हैं, न तो संत थे और न ही साधु। तो फिर विरोध प्रदर्शन को इस तरह दिखाने के लिए गेरुआ कपड़ों का इस्तेमाल क्यों किया गया?

गुमराह बच्चों को सजा नहीं, सही राह दिखाना समाज की जिम्मेदारी - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा एक वीडियो संदेश में जंतर–मंतर पर हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना में उन्हें और उनकी दिवंगत माता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, लेकिन वह संबंधित युवाओं को सजा दिलाने के बजाय उन्हें सही राह दिखाने के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंतर–मंतर पर जो कुछ हुआ, उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि कुछ "शरारती बच्चों" ने बेहद अभद्र और असभ्य भाषा का प्रयोग किया, जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि घटना दुखद है, लेकिन वह इस विषय पर कटुता के बजाय सकारात्मक सोच और सुधार की भावना के साथ बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बचपन में गलतियां होना स्वाभाविक है और यही उम्र गलतियों से सीखने तथा उन्हें सुधारने का अवसर भी देती है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर समाज में व्याप्त आक्रोश को वह समझते हैं। उनके अनुसार, यह एक "कल्चरल शॉक" है कि देश की बेटियां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय इन युवाओं को गले लगाकर सही रास्ता दिखाने का है। उन्होंने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं और उन्हें सही दिशा देना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार, उन्हें सजा देना, अदालतों के चक्कर लगवाना या सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह संबंधित युवाओं को माफ करना चाहते हैं और समाज से भी उनकी इस भावना को स्वीकार करने की अपील की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कभी–कभी दांतों के बीच जीभ आ जाती है और खून भी निकल आता है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज शनिवार को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, "1 अगस्त से दिल्ली की महिलाओं के जीवन में सम्मान का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल गया है। किसी बहन के लिए यह अपने नाम की पहली बचत होगी, किसी के लिए दवा, किताब या घर की कोई जरूरी चीज और किसी के लिए यह एहसास कि अब अपनी हर आवश्यकता के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।" सीएम में लिखा, 'दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर पात्र महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपए का आर्थिक संबल मिलेगा। यह राशि केवल खाते में नहीं जाएगी, यह आत्मविश्वास जगाएगी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएगी और जीवन को अपने ढंग से जीने का साहस देगी। सभी पात्र महिलाएं दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेवसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। यह योजना सरकार की उन अहम कल्याणकारी पहलों में से एक है, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना है। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने 2026–27 के बजट में 5,110 करोड़ रुपए रखे हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि जब यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तो दिल्ली भर में 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। पात्रता के नियमों के तहत, 21 से 60 साल की उम्र की वे महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एंटी पेपर लीक संशोधन कानून को दी मंजूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देशभर में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया पर शिकंजा कसने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह संशोधित कानून लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करना और छात्रों के भविष्य की रक्षा करना है।कानून एवं न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी कर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले संसद के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस विधेयक को पारित किया था। राज्यसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। हालांकि मतदान के दौरान इंडिया गठबंधन के कई विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके एक दिन पहले लोकसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। विधेयक के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि देश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो गया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक नेशनल अवॉर्ड से किया सम्मानित

मुबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अजीत डोभाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद उपस्थित अतिथियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के ट्रस्टी रोहित तिलक सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक व्यक्ति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए इस समारोह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रसेवा के विचारों को एक बार फिर स्मरण कराया। 81 वर्षीय अजीत डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और अभी इस पद पर बने हुए हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने मिजोरम, सिक्किम, पंजाब और जम्मू–कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में काम किया है। इस्लामाबाद और लंदन में भारतीय मिशनों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डोभाल भारत–चीन सीमा वार्ता के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। 2017 में डोकलाम गतिरोध को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने में उनकी भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर उनके रणनीतिक फैसलों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में महाराष्ट्र मंडल, पुणे द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति, विकास और सामाजिक उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपए की 'समुद्र मंथन' योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली 'समुद्र मंथन' (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना) को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना को वित्त वर्ष 2030–31 तक लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने और अपतटीय ऊर्जा संसाधनों के दोहन को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। सरकार के अनुसार, 'समुद्र मंथन' योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रस्तुत आधुनिक 'समुद्र मंथन' के विजन को साकार करेगी। योजना का उद्देश्य भारत की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन में तेजी लाना तथा 'विकसित भारत' के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। योजना के तहत अपतटीय अन्वेषण की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले सिस्मिक डेटा का व्यापक संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या, गहरे एवं अति–गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेज ड्रिलिंग, नए और कम खोजे गए बेसिनों में वैज्ञानिक अन्वेषण, अपतटीय उत्पादन एवं निकासी के लिए साझा बुनियादी ढांचे का विकास तथा एकीकृत तेल एवं गैस विनिर्माण एवं सेवा पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना शामिल है। इसके अलावा डिजिटल कार्यक्रम प्रबंधन, क्षमता विकास, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने, हितधारकों की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि 'समुद्र मंथन' योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट (एमएमटीओई) से अधिक संभावित भंडार के विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे अपतटीय अन्वेषण गतिविधियां बढ़ेंगी।

केजरीवाल ने भाजपा के दावों पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को देश में ई20 पॉलिसी लागू करने के विरोध में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक नेशनल टाउनहॉल प्रोग्राम किया। पत्रकारों से बात करते हुए, आप के राष्ट्रीय संयोजक ने पेट्रोल–ब्लेंडेड इथेनॉल पॉलिसी के बारे में केंद्रीय मंत्रालय के बयानों में विरोधाभास पर सवाल उठाए और दावा किया कि इस विषय पर कोई ठोस स्टडी नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि ई20 पॉलिसी लोगों पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार की ई20 पॉलिसी लागू करने में दिलचस्पी पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि गाड़ियों में पेट्रोल–ब्लेंडेड इथेनॉल होने की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज कम हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ वे कहते हैं कि ई20 अच्छा है, दूसरी तरफ वे कहते हैं कि ई20 बुरा है। एक मंत्रालय कहता है कि 2 से 5 प्रतिशत का अंतर है, जबकि दूसरा मंत्रालय 4 प्रतिशत कहता है। उन्होंने कोई स्टडी नहीं की हैय वे बस लोगों पर यह पॉलिसी थोप रहे हैं। गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज कम हो रहा है। सरकार लोगों पर इसे क्यों थोप रही है? इसमें सरकार की क्या दिलचस्पी है? ई20 पेट्रोल अच्छा नहीं है। केजरीवाल के साथ–साथ, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी ई20 पॉलिसी को लागू करने का विरोध किया।

मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर के एक के पास से बम बनाने के तरीके की मिली पर्ची मिली

पुलिस व सुरक्षा एजेंसी छानबीन मे जुटी

अयोध्या।मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में एक छात्र के पास से बम बनाने के तरीके लिखी एक पर्ची मिली है।पुलिस के छानबीन में पता चला के गिरफ्तार किया गया छात्र फिल्म देखते समय बम बनाने के तरीका पर्ची पर नोट कर लिया था।अयोध्या पुलिस व सुरक्षा एजेंसी में हड़कंप मच गया।मिली पर्ची मे कुछ कैमिकल फॉमूले और उनके डायग्राम भी बने हैं।इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पूजा मिली तो वह सतर्क हो गए और छानबीन में जुड़ गए।हिरासत में लिए गए आरोपी छात्र की पहचान सरफराज बलरामपुर के रूप में हुई जो अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन (पैरामेडिकल) प्रथम वर्ष का छात्र है वह मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल में रहता है।। छात्र ने पुलिस को बताया कि वो रात में ड्यूटी के दौरान लैपटॉप पर फिल्म देख रहा था। फिल्म में बम बनाने का तरीका सिखाया जा रहा था।उसी तरीके को उसने पर्ची में नोट कर लिया था।वहीं, पुलिस जांच में सामने आया कि पर्ची में बम बनाने के तरीके से लेकर विस्फोटक उपकरणों की संरचना, आकार और उसकी तीव्रता के बारे में काफी गहन रिसर्च के नोट्स लिखे हैं।फिलहाल छात्र को अयोध्या पुलिस लाइन ले जाया गया है।वहां उससे एसओजी, एसटीएफ स्पेशल ब्रांच और आईबी के अधिकारी उससे पूछताछ किया।एक्स–रे लैब में सरफराज की ड्यूटी रात 10 से लेकर सुबह 8 बजे तक रहती है। शुक्रवार (31 जुलाई) रात सरफराज के साथ अभिषेक और सुभाष की भी ड्यूटी लगी थी। तीनों की ड्यूटी सुबह 8 बजे खत्म होने के बाद सफाईकर्मी लैब की सफाई करने पहुंचे। वहां उन्हें एक पर्ची मिली।सरफारज को बुलाकर हिरासत में लिया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए पुलिस लाइन ले गई। वहां एसओजी,एसटीएफ स्पेशल ब्रांच और आईबी के अधिकारियों ने सरफराज से पूछताछ की।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली अयोध्या पंकज सिंह ने बताया गिरफ्तार किए गए आरोपी सरफराज शुक्रवार की रात लैपटॉप पर एक फिल्म देख रहा था जिसमें बम बनाने का तरीका सिखाया जा रहा था।प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली अयोध्या श्री सिंह ने बताया कि वह भी उस तरीके को सीखने की कोशिश की।लेकिन, तब तक मुझे नींद आ गई और मैं सो गया था।इसके बाद वो पर्जी इन लोगों के हाथ गई।

उपराज्यपाल सिन्हा और महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम आतंकी हमले की निंदा की

श्रीनगर, (एजेंसी)। शनिवार को जम्मू–कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की निंदा की है। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कुलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद मैंने डीजीपी नलिन प्रभात और सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों से बात की। मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने सुरक्षा बलों को अपने ऑपरेशन तेज करने और आतंकवादियों को खत्म करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के एक और घायल मजदूर को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूं। जम्मू–कश्मीर प्रशासन और पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की हत्या की मैं कड़ी निंदा करता हूं। वे अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से दूर जाकर कड़ी मेहनत करते हैं। हिंसा की ऐसी बेमतलब की घटनाओं में उन्हें निशाना बनाना अकल्पनीय रूप से क्रूर है। जम्मू–कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शाम के समय आतंकवादियों ने कुलगाम के केलम गांव में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले इन दो मजदूरों पर गोली चलाई और उन्हें घायल कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों को तुरंत बेहतर इलाज के लिए अनंतनाग शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद, छत्तीसगढ़ के दीपक और उत्तर प्रदेश के भूपिंदर नाम के इन दोनों घायल मजदूरों की अस्पताल में गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई।

संपादकीय

करप्शन अगेंस्ट इंडिया

2004 से लेकर 2014 तक देश में यूपीए शासन रहा, जिसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। इस सरकार पर 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स, कोयला ब्लॉक आबंटन और 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल लाने के नाम पर ही लंबा आंदोलन किया। जिसमें भाजपा और मीडिया का पूरा साथ रहा। तब फिल्म जगत के लोगों ने भी डॉ.मनमोहन सिंह का खूब मजाक उड़ाया। तब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए उसे पिंजरे का तोता कहा था। कांग्रेस के खिलाफ बने इस माहौल का ही असर था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनी और इसके बाद कभी कांग्रेसमुक्त भारत तो कभी विपक्षमुक्त भारत बनाने की कोशिशें हुईं। यह और बात है कि भाजपा ये कोशिशें नाकाम रहीं, मगर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को इसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये सारी बातें इस समय करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आबंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामले को बंद कर दिया और उन्हें समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने 2014 में दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर साफ कहा था कि मनमोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसके बावजूद विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी थी और 2015 में उन्हें आरोपी के रूप में तलब कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि विशेष अदालत के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ठुकराने का कोई ठोस कारण नहीं था, इसलिए अदालत ने उस आदेश को रद्द करते हुए मामला गुण–दोष के आधार पर बंद कर दिया। चूंकि 27 दिसंबर 2024 में मनमोहन सिंह का निधन हो चुका था, इसलिए यह फैसला उन्हें मरणोपरांत कानूनी राहत देने वाला माना जा रहा है।डा. सिंह अपने निर्दोष होने के फैसले को सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जनवरी 2014 में अपनी आखिरी प्रेस कांफ्रेंस में मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा था, श्मैं इस मामले में थोड़ा दुरुखी महसूस करता हूं क्योंकि मैंने ही इस बात पर जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम आबंटन पारदर्शी और निष्पक्ष हो। मैं ही था जिसने जोर देकर कहा था कि कोल ब्लॉक का आबंटन नीलामी के आधार पर हो, लेकिन इन तथ्यों को भुला दिया गया। इस मामले में विपक्ष का अपना स्वार्थ निहित था। कुछ मौकों पर मीडिया उनके हाथ का खिलौना भी बन गया।ष उन्होंने कहा था कि श्इसलिए मेरे पास इसकी हर वजह है कि जब भी इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, हम बेदाग बाहर आएंगे। मनमोहन सिंह ने कहा, श्मैं मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति आज के मीडिया के मुकाबले ज्यादा उदार होगा। महज 12 साल पहले का ऐसा राजनैतिक माहौल अब सपने जैसा नजर आता है कि प्रधानमंत्री प्रेस कांफ्रेंस किया करते थे, अपने ऊपर और अपनी सरकार पर लगे आरोपों को लेकर जवाब देते थे। अब न तो प्रधानमंत्री प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, न मीडिया के लोग उनसे भ्रष्टाचार पर बातें करते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तो ताजा प्रकरण है, पिछले बारह बरसों में कई और ऐसे प्रकरण हुए, लेकिन हर बार नैरेटिव बदल कर सरकार को जवाबदेही से निकलने का मौका मीडिया देता रहा। फिलहाल नरेन्द्र मोदी तो यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह जानते थे कि सच कभी पराजित नहीं होता, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने साथ होने वाले न्याय की बात कह दी थी।दरअसल कोयला ब्लॉक आबंटन में यह आरोप लगाए गए कि सरकार ने निजी कंपनियों को बिना बोली लगाए आबंटन कर दिया, इससे कम से कम 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यूपीए सरकार में कोयला सचिव रहे पी.सी. पारेख, इस मामले में व्हिसलब्लोअर माने जाते हैं।

लोकतंत्र के लिए खतरनाक पक्षपाती रवैया

बुधवार को एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई बार–बार स्थगित हुई, क्योंकि विपक्षी सांसदों के बयान सत्तापक्ष को मंजूर नहीं थे। हंगामे के बीच पेपर लीक विरोधी विधेयक तो लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। किंतु लोकसभा में केवल सत्तापक्ष की ध्वनि के लिए जगह बची है, यह बात फिर स्थापित हो गई। 2024 में जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, भाजपा सरकार पहले से ज्यादा उद्वेलित और असहज दिखने लगी है। राहुल गांधी ने कहा ही था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे सदन में नहीं आते। अब शायद यही बात गृहमंत्री अमित शाह पर भी लागू हो जाएगी।राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, जो सत्तापक्ष को इतने आपत्तिजनक लगे कि राहुल गांधी से माफी की मांग की जाने लगी। उनका भाषण पूरा नहीं हो पाया, कई बार उन्हें टोका गया। जिस पर राहुल गांधी को यहां तक कहना पड़ा कि अगर इस सदन में केवल भाजपा को बोलने का अधिकार है, तो फिर मैं चुप बैठ जाता हूं। हमेशा की तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला फिर निष्पक्ष रवैया दिखाने में नाकाम रहे। वे भले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष कहकर अपनी बात रख रहे हों, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के लिए मान उनके व्यवहार में नजर नहीं आया। यही बात सत्तापक्ष के सभी सांसदों पर लागू होती है। खासकर संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू पर, जिनका एकमात्र काम इस समय मोदी–शाह का बचाव करना नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने पेपर लीक आंदोलन में उतरे छात्रों पर गोलियां चलाने के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। जिस पर सत्तापक्ष भड़क उठा। किरण रिजीजू ने कहा कि इस बात के सबूत दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो फिर ऐसा कहना ठीक नहीं है, आप माफी मांगिए। रिजीजू ने यह भी कहा कि ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर किया है। क्या ऐसा कहना ठीक होगा।बात सही है कि सदन में किसी का भी नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन राहुल गांधी किसी की भी बात नहीं कर रहे थे, वे बाकायदा गृहमंत्री अमित शाह की बात कर रहे थे, जिनके अधीन पुलिस प्रशासन आता है, जिनके जिम्मे देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व है। जंतर–मंतर पर छात्रों पर लाठी और आंसू गैस के गोले के अलावा पैलेट गन से वार किया गया, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें लगने की खबरें हैं। एक छात्र को तो राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने दिखाया भी था, जिसकी आंख फूटने का खतरा बना हुआ है। एक पत्रकार को भी पैलेट गन से चोट लगी है। इसी तरह बिहार में पुलिसकर्मी अभिषेक पटेल के हाथों में एके 47 लेकर छात्रों की तरफ निशाना साधे दिखे हैं, उसके वीडियो सामने हैं, इसी आधार पर उन्हें निलंबित भी किया गया है। तो क्या यह सवाल अमित शाह से नहीं किया जाएगा कि क्या उन्होंने छात्रों के खिलाफ बंदूकें तानने के आदेश दिया, गोली चलाने के आदेश दिए। अगर नहीं दिए और फिर भी इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, तो यह ज्यादा गंभीर बात है कि पुलिस गृहमंत्री को अंधेरे में रखकर काम कर रही है।दोनों ही सूरतों में जवाब अमित शाह को देना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस समय भाजपा सरकार देश को अंधेरे में रखने का ही काम कर रही है। छात्रों पर पुलिसिया ज्यादती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्या सरकार वहां जवाब नहीं देगी। अगर कानूनी अदालत में सरकार बोल सकती है, तो फिर जनता के चुने प्रतिनिधि जब यही सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब देने से क्यों बच रही है।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों पर मोदी सरकार के तर्कपूर्ण जवाब

नीरज

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर ऐसी बहस छिड़ी, मानो लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थाओं में से एक का भविष्य न्यायालय के कटघरे में खड़ा हो। एक ओर संविधान की आत्मा और निष्पक्ष चुनाव की कसौटी पर सवाल उठाते न्यायाधीश थे तो दूसरी ओर

संसद की सर्वोच्चता और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पक्ष मजबूती से रखती केंद्र सरकार। सवालों और जवाबों का यह सिलसिला कई बार अदालत की बहस से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं पर गहन विमर्श में बदल गया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले यही सवाल उछाला कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का पद लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उनके चयन की प्रक्रिया ऐसी क्यों न हो, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह न रहे? अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होकर काम करे, इतना पर्याप्त नहीं हैय उसे स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए। इसी संदर्भ में अदालत ने सरकार से सीधा प्रश्न किया कि संसद ने 2023 का कानून बनाते समय चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (ब्श्रप्) को बाहर रखने का निर्णय आखिर किस आधार पर लिया? पीठ ने याद दिलाया कि सीबीआई निदेशक और लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों के चयन में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका स्वीकार की गई है, फिर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के मामले में यह व्यवस्था क्यों बदली गई? केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क का जोरदार प्रतिवाद किया। उन्होंने अदालत से कहा कि बहस की शुरुआत इस धारणा से नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा और पवित्रता है तथा जनता को उनके निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए। तुषार मेहता ने सवालिया अंदाज में कहा, ष्यदि प्रधानमंत्री के फैसलों पर भरोसा ही नहीं किया जाएगा, तो क्या फिर मंत्रिमंडल के गठन के समय भी किसी पूर्व न्यायाधीश या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेना अनिवार्य कर दिया जाए?ष उन्होंने यह भी दलील दी कि केवल इसलिए कि कार्यपालिका के पास संख्यात्मक बहुमत है, यह मान लेना उचित नहीं कि वह संविधान विरोधी या दुर्भावनापूर्ण निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के तीनों अंग यानि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और एक संस्था दूसरी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन अदालत ने तुरंत स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य प्रधानमंत्री पर अविश्वास जताना नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का है जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा, ष्हम यह नहीं कह रहे कि वर्तमान समिति ने निष्पक्षता नहीं बरती है। लेकिन जैसे न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, उसी प्रकार चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में भी निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए। इसी दौरान अदालत ने सरकार से एक और तीखा सवाल पूछा। पीठ ने याद दिलाया कि पहले भी अदालत ने निर्वाचित सरकार पर भरोसा जताते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री न बनाने की अपेक्षा की थी। ऐसे में आज सरकार में कितने मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं? इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी तय होती है। हम आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 2023 के उस कानून को लेकर है, जिसके तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री वाली चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। बाद में संसद ने कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी अदालत से कहा कि संसद की विधायी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। उनका कहना था कि केवल इसलिए कि कोई दूसरा मॉडल बेहतर हो सकता है, संसद द्वारा चुनी गई व्यवस्था को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ष्संसद को इस प्रकार बाधित नहीं किया जा सकता।ष सरकार ने अपने हलफनामे में भी यही रुख दोहराया। केंद्र ने कहा कि यह आशंका पूरी तरह काल्पनिक है कि चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता स्वतः प्रभावित हो जाएगी। सरकार ने याद दिलाया कि सात दशक से अधिक समय तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह कार्यपालिका द्वारा होती रही, लेकिन इस दौरान देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी बाधित नहीं हुए। इसलिए केवल आशंकाओं के आधार पर कानून को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान केंद्र ने यह आग्रह भी किया कि मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं, इसलिए इसे बड़ी संविधान पीठ को भेजा जाए। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता डी. शेषाद्रि नायडू, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण और संजय पारिख ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि लगभग 20 दिन तक विस्तृत सुनवाई चलने के बाद अब इस आधार पर मामला बड़ी पीठ को भेजने की मांग करना केवल सुनवाई को टालने का प्रयास है। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की गई है। अब निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह निर्णय केवल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, संसद की विधायी शक्ति और जनता के भरोसे के बीच संतुलन की नई संवैधानिक रेखा भी खींच सकता है।

बढ़ते अरबपति गतिशील इकोनोमी के परिचायक

राजेन्द्र

एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि देश की इकोनोमी में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दिनों में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों का ही विश्लेषण करें तो दो बातें साफ हो जाती है कि देश में अरबपतियों की संख्या में बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी और इंकमटैक्स रिटर्न भरने वालों की भी संख्या में इजाफा हो रहा है। संसद में पेश आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ हो रहा है कि आयकर रिटर्न में 100 करोड़ से अधिक की आय बताने वालों की संख्या 2021–22 की 142 से बढ़कर 576 हो गई है। आयकर रिटर्न के अनुसार पिछले सालों एक अरब से अधिक आय वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसे गतिशील अर्थ व्यवस्था का परिचायक माना जा सकता है। पिछले पांच साल के आंकड़ों का ही विश्लेषण किया जाएं तो देश में बेरोजगारी की दर में भी कमी आई है। हांलाकि सरकार इसके लिए अपनी लोककल्याणकारी नीतियों को श्रेय देती है। आयकर प्रक्रिया में सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सीधा लाभ, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन , पानी बिजली आदि आदि की जनहितकारी योजनाओं और निवेशोन्मुखी माहौल से देष में तेजी से सुधार का माहौल बना है। हांलाकि देश के कुल परिसंपत्तियों में 50 फीसदी से अधिक लोग केवल 2 प्रतिशत की ही हिस्सेदारी रखते हैं। अच्छी बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही है और युवकों के साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक पध्क्ष यह है कि समन्वित प्रयासों से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए क्षेत्रों को तेजी से व योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया गया है। परंपरागत क्षेत्रों के साथ ही नए क्षेत्रों में अवसर खुले हैं और इसका सबसे अधिक लाभ युवा पीढ़ी उठा रही है। एक आंकड़ें के अनुसार 425 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले 3040 में से 1696 ऐसे उद्यमी है जो नई पीढ़ी और पहली पीढ़ी के हैं। नई पीढ़ी से मतलब यह है कि यह वे नए लोग है जो पंरपरागत या धनकुबेरों के परिवारों से नहीं आते अपितु अपने स्तर पर इस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। यही अर्थव्यवस्था का सकारात्मक पक्ष हो जाता है। सरकारी नीतियों और युवाओं में नया करने की ईच्छा शक्ति का परिणाम है कि नए क्षेत्रों में स्टार्टअप या एमएसएमई के मध्यम से युवाओं ने पहल की और अर्थ व्यवस्था को गति देने के साथ ही निवेश, रोजगार के अवसर विकसित किये। सरकार ने भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानि की पीएलआई से युवाओं को जोड़कर कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त हुए हैं। साल दर साल आयकर रिटर्न भरने वाले और आयकर देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। यह सब सरकार की सकारात्मक नीतियों से ही संभव हो सकता है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सरकार की नीतियों का अर्थ व्यवस्था को गति देने में खास भूमिका होती है। आज दुनिया के देशों में ईज ऑफ डूइंग पर जोर दिया जा रहा है। देशों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और देशी विदेशी निवेश बहुत कुछ सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। बुनियादी ढांचा विकास, उद्योगों को प्रोत्साहन, सेवा क्षेत्र में विस्तार, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, जीएसटी एक देश एक कर की नीति, डिजिटल भुगतान और विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार से औद्योगिक माहौल बनता है। एक बात और की एमएसएमई आर्थिक विकास की रीढ होती है। इसे ग्रोथ इंजन भी कहा जा सकता है क्योंकि इससे अर्थ व्यवस्था को गति मिलती है तो स्थानीय स्तर पर बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर भी एमएसएमई सेक्टर में ही विकसित होते हैं। यही कारण है प्रोडक्सन लिंक इंसेटिंव जैसी योजनाओं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से युवा रोजगार मांगने की जगह रोजगार प्रदाता बनने का सपना देखता है और इसमें कोई दे राय नहीं कि एमएसएमई सेक्टर में अधिक रोजगार के अवसर विकसित होते हैं। अर्थ व्यवस्था को गति मिलती है। हांलाकि बड़े उद्योगों का अपना महत्व हे और उससे इंकार नहीं किया जा सकता। एक और बात यह है कि देश में निवेशोन्मुखी माहौल बन रहा है। राज्यों द्वारा अब निवेशकों को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिए अन्य राज्यों के साथ ही प्रोस्पेक्टिव विदेशों में रोड शो सहित विभिन्न आयोजन कर निवेश का माहौल बनाया जाता है। राज्यों द्वारा निवेश सम्मेलन और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए

आयोजन आम होते जा रहे हैं। इसके परिणाम भी आने लगे हैं। यह भी साफ है कि उद्योग लगाने के लिए निवेश आयेगा तो रोजगार, कारोबार के साथ ही नई तकनीक और इसके साथ ही अन्य कई चीजें आयेगी और उसका लाभ देश और देश की अर्थ व्यवस्था को ही मिलेगा। सवाल एक और उभरता है कि अमीर–गरीब की खाईं अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक पक्ष यह है कि रोजगार और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नागरिकों की आय बढने लगी है और इसका समाज के समग्र विकास पर असर पड़ता है। आय बढ़ेगी या रोजगार उपलब्ध होगा तो रहन–सहन, जीवन यापन के स्तर में सुधार होगा। लोगों की आय बढ़ेगी और आय से बाजार में मांग आपूर्ति में बदलाव आयेगा और इससे इकोनोमी को गति मिलेगी। अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी अच्छी बात है पर अमीर गरीब के बीच खाईं पाटने के प्रयास अभी नाखाफी ही लग रहे हैं।

युवाओं के सत्याग्रह ने अपने पीछे कुछ सबक छोड़े

राजेश

आंदोलन ने सत्ता में बैठे लोगों को अपनी कार्यशैली में जरूरी बदलाव पर विचार का मौका दिया है। सत्ता के दुरुपयोग, उसके केंद्रीकरण के खिलाफ लोगों के उठ खड़े होने के बारे में चेतावनी दी है। प्रधान के इस्तीफे से निश्चय ही दूसरे मंत्री सतर्क हो जाएंगे। दरअसल, यह सुरक्षा के अघोषित और अदृश्य कवच में दरार आने का संकेत है। भाजपा सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा

नहीं होने का मिथक टूट गया है। जंतर–मंतर पर एक माह तक चले युवाओं के आंदोलन ने कुछ सबक सिखाए हैं, कुछ मुद्दों पर रोशनी डाली है, कुछ उम्मीदें जगाई हैं और साहस, सत्याग्रह की अहमियत को सामने रखा है। यह आंदोलन कई मायनों में अद्वितीय है। उसने लोकतंत्र, संविधान के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी और सत्ता का दुरुपयोग करने वाली सरकार को अपने कदम पीछे हटाने के लिए विवश किया है। इससे पहले किसान आंदोलन के कारण सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेना पड़े थे। लेकिन दोनों आंदोलनों में कुछ फर्क है। किसान आंदोलन का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तरप्रदेश में अधिक था। वहीं युवाओं की हलचल तेजी से फैल रही थी। उसमें छात्रों के परिजन शामिल हो रहे थे। भाजपा का समर्थन करने वाले मध्यम वर्ग में भी बेचौनी थी।बहुत कम लोगों को शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की उम्मीद थी। राजनीतिक पर्यवेक्षक सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ नेता के बयान का जिक्र करते थे कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। संतोष का विषय है कि युवाओं ने सरकार को जवाबदेही और जिम्मेदारी का अहसास कराया है। उनके आंदोलन के कारण पहली बार शिक्षा राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में आ गई है। छात्रों ने संदेश दिया है कि अब भी अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से मनमानी करने वाली सरकार पर अंकुश लगाना संभव है। शासकों के इशारों पर चलने वाली संस्थाओं को सचेत होने का अवसर दिया है। भारत में संवाद, विरोध और अहिंसक तरीके से अपनी अपेक्षाओं को जाहिर करने की परंपरा पुरानी है। इसके सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी हैं। उनके सत्याग्रह ने भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद कई मौकों पर जनमत जगाने वाले आंदोलन हुए हैं। 1970 के दशक में गुजरात से शुरू हुए छात्रों के नवनिर्माण आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की जमीन तैयार की थी। फिर 2011–12 के अन्ना आंदोलन ने यूपीए सरकार की चुनावी हार का रास्ता बनाया। इन आंदोलनों में गैर–राजनीतिक संगठनों, आम लोगों के अलावा राजनीतिक दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। छात्रों के मौजूदा आंदोलन के पीछे सुनियोजित रणनीति और कार्यक्रम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई। उसने दिल्ली में धरना शुरू किया और इसकी गूंज पूरे देश तक पहुंच गई। चंद दिनों के भीतर हजारों युवा दिल्ली में जुट गए। सरकार के दमन ने आग में घी डाला। पुलिस ने आंसू गैस, पैलेट गन, लाठीचार्ज के जरिये जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। इंटरनेट बंद करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युवा शक्ति की क्रिएटिविटी से उपजे हास्य, व्यंग्य की पैनी धार के सामने तमाम तरीके बेअसर हो गए। छात्रों के पोस्टर और मीम भारी पड़े। सोशल मीडिया ने आंदोलन की हलचल को हर जगह पहुंचा दिया।

सरकार की जी–हुजूरी करने और विपक्षी पार्टियों को हमेशा निशाना बनाने वाले गोदी मीडिया के पैंतरे बेकार गए। आंदोलन का स्वरूप और उसकी रफ्तार सरकार की कल्पना से परे थी। उसने छात्रों से लगातार बातचीत की। लेकिन छात्र अपने रुख पर अडिग रहे। आंदोलन के पीछे पाकिस्तान, चीन का हाथ होने जैसे पुराने नकारात्मक दांव भी काम नहीं आए। विरोध को देशद्रोह और राष्ट्रविरोधी बताने का जाना–पहचाना हथियार भी कुंद साबित हुआ। यहां प्रमुख विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने छात्रों का समर्थन करने के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखने की सावधानी बरती। इस चतुराई के कारण आंदोलन को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित घोषित नहीं किया जा सका है। सोनम वांगचुक के लंबे अनशन ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका छात्रों के विरोध ने शिक्षा व्यवस्था की कई मूलभूत समस्याओं, उच्च शिक्षण संस्थाओं की नियुक्तियों में पेशेवर मापदंडों को दरकिनार रखने सहित कई खामियों पर फिर बहस की जरूरत बताई है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थाओं में अहम पदों पर नियुक्तियों में योग्यता, विद्वता, पेशेवर क्षमता की बजाय विचारधारा को तवज्जो दी गई है। स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव पर भी विचारधारा हावी है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गहराते संकट ने छात्रों को उद्वेलित किया है। साल दर साल तैयारियों के बाद जब पेपर लीक हो जाएं, समय पर रिजल्ट आने का कोई भरोसा न रहे तब असंतोष का विस्फोट होना स्वाभाविक है। सत्याग्रह ने शिक्षा और रोजगार से जुड़े कुछ बिंदुओं को चर्चा के केंद्र में रख दिया है। यहां हम युवाओं के मुद्दों पर गौर करेंगे। युवाओं की हताशा बढ़ती बेरोजगारी से जुड़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकानॉमी के अनुसार– जॉब्स में 15 साल और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2016–17 के 42.7प्रतिशत से घटकर मार्च 2026 में 38.7 प्रतिशत रह गई। इसलिए समस्या के सभी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। मई में नीट की पहली परीक्षा में बीस लाख से अधिक छात्र बैठे थे। प्रश्नपत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद एक दर्जन से अधिक छात्रों के आत्महत्या करने की खबरें आईं। भारत में दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं से मौतों पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 8068 छात्रों ने आत्महत्या की थी। यह संख्या 2024 में 14288 रही। अंग्रेजी अखबार हिंदू में प्रकाशित खबर में बताया गया है, संसद में शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि छात्रों की आत्महत्या के कारणों में अकादमिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य, धन की तंगी और व्यक्तिगत टकराव शामिल हैं। रिपोर्ट में परीक्षा में विफलता को प्रमुख कारण बताया गया है। 2014 से 2024 के बीच छात्रों की आत्महत्याओं के कुल मामलों में 21प्रतिशत छात्रों ने इस कारण जान दे दी। इस अवधि में सिर्फ 2021 को छोड़कर हर साल दो हजार से अधिक छात्रों ने विभिन्न परीक्षाओं में विफलता की वजह से जीवन गंवा दिया। राजनीतिक विश्लेषण सेवा प्रश्नपत्रों के लीक होने से कई तरह का बोझ पड़ता है। छात्रों और उनके परिवार के लिए परीक्षाओं की तैयारी महंगी पड़ती है। हर साल बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग संस्थाओं की शरण में जाते हैं। शिक्षा पर विस्तृत मॉड्यूलर सर्वे 2025 (सीएमएस–ई) के अनुसार हायर सेकंडरी के 37प्रतिशत शहरी और ग्रामीण छात्रों ने प्राइवेट कोचिंग ली है। इस स्तर पर प्रति छात्र कोचिंग का खर्च 6384 रुपए आया है। शिक्षा के संबंध में कुछ आंकड़े चिंताजनक हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के शिक्षा बजट में भारी गिरावट आई है। यह यूपीए सरकार के अंतिम वर्ष 2013–14 के 4.6 प्रतिशत से घटकर 2025–26 में 2.5 प्रतिशत पर आ पहुंचा है। शिक्षा पर खर्च के मामले में राज्यों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। संविधान की सातवीं अनुसूची में शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। इसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। 2013–14 में शिक्षा के खर्च में राज्यों का हिस्सा 17प्रतिशत के आसपास था। अब यह करीब 13प्रतिशत है।

एल. पी. एस. में मंगल मिशन की महिला वैज्ञानिकों का सम्मान

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। फिक्की फ्लो लखनऊ चौप्टर ने लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज के सहयोग से ष्अद्वितीय दृ भारत के मंगल मिशन की महिला वैज्ञानिकों का सम्मानष विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ैत्व) के ऐतिहासिक मंगल मिशन एवं अन्य महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिकों के असाधारण कार्यों का सम्मान करना तथा छात्राओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर लखनऊ सहित बाराबंकी, हरदोई एवं आसपास के जनपदों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की कक्षा 11 एवं 12 की 1200 से अधिक छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में इसरो की प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की प्रेरणादायी उपस्थिति रही, जिनमें इसरो के तीन वैज्ञानिक रूपा एम. वी., मौमिता दत्ता तथा अशोक कुमार शर्मा शामिल रहे। वैज्ञानिकों ने अपने प्रेरक अनुभव साझा करते हुए भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित (ैज्म्ड) के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। यह कार्यक्रम फिक्की फ्लो लखनऊ की अध्यक्षा सिमरन साहनी एवं उनकी कार्यकारिणी समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा छात्राओं को देश की अग्रणी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान कर उनमें नवाचार, वैज्ञानिक सोच एवं अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना था। लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेज ने इस कार्यक्रम में इवेंट पार्टनर के रूप में सहभागिता निभाई। संस्थान के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉ. एस. पी. सिंह (सांसद) ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना, आत्मविश्वास एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ष्अद्वितीयष कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा एवं भारत की अंतरिक्ष यात्रा में महिलाओं के उत्कृष्ट नेतृत्व का एक अविस्मरणीय उत्सव सिद्ध हुआ, जिसने उपस्थित छात्राओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की नई ऊर्जा प्रदान की।

'मेडिकल असेसमेंट कैम्प का किया गया आयोजन'

जौनपुर । जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के आदेशानुसार और बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर यादव के निर्देश पर विकास खण्ड सिरकोनी के खण्ड शिक्षा अधिकारी अमरेश कुमार की अध्यक्षता में बी आर सी सिरकोनी के बगल स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाकराबाद के परिसर में दिनांक 31 जुलाई 2026 को दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता का चिन्हीकरण करते हुए उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल असेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया। इस कैंप में कुल 46 बच्चों का यू डी आई डी कार्ड हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया जिसके अन्तर्गत 15 बच्चे लोकोमोटर दिव्यांगता, 10 बच्चे बुद्धि अक्षमता, 06 बच्चे दृष्टिबाधित, सेंरेब्रल पाल्सी के 04 बच्चे तथा शेष अन्य 11 बच्चे बहु दिव्यांगता के अन्तर्गत यू डी आई डी कार्ड हेतु पात्र पाए गए। कैम्प में उपस्थित मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों द्वारा इन सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र व यू डी आई डी कार्ड जारी किया गया। मेडिकल असेसमेंट कैम्प के मेडिकल बोर्ड में क्रमशः डा.अजय सिंह अस्थि रोग विशेषज्ञ, डा.दीपशिखा नेत्र रोग विशेषज्ञ,डा.दिलीप चौरसिया बुद्धि अक्षमता विशेषज्ञ,डा.वृजेश कनौजिया श्रवण ह्रास विशेषज्ञ, फिजियोथैरेपिस्ट डा.पी.डी.तिवारी तथा आडियोलॉजिस्ट डा.सुरेन्द्र प्रजापति ने संयुक्त रूप से एक–एक बच्चे की जांच करते हुए उनकी दिव्यांगता का परीक्षण किया। आज के इस मेडिकल असेसमेंट कैम्प में बच्चों को उपस्थित कराने और उनकी जांच में सहयोग करने में विकास खण्ड सिरकोनी के समस्त स्पेशल एजुकेटर क्रमशः प्रमोद दूबे, राम मनोहर भारती, शक्ति सिंह तथा रेनू सिंह का विशेष योगदान रहा तथा कार्यक्रम की रिपोर्टिंग न्याय पंचायत नेहरूनगर के नोडल शिक्षक संकुल डॉ.आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई।

50 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर पुलिस मुठभेड़ में घायल, साथी समेत गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में खुटहन थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी एवं अंतरजनपदीय हिस्ट्रीशीटर बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में शनिवार को जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी शाहगंज गिरेन्द्र सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर थानाध्यक्ष लक्ष्मण विक्रम सिंह के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत खुटहन पुलिस सुईथाखुर्द नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रिंकू यादव यादव निवासी भेला, थाना सरपतहाँ (जौनपुर) के बाएं पैर में गोली लग गई। उसका साथी सत्यम लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर (अंबेडकर नगर) को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल रिंकू यादव को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटहन भेजा गया। रिंकू यादव थाना सरपतहाँ का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी तथा अयोध्या सहित विभिन्न जनपदों में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर एक्ट और शस्त्र अधिनियम समेत 38 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार सत्यम लोना के विरुद्ध भी कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

आत्महत्या मामले में नायब तहसीलदार पर दुष्कर्म व उत्पीड़न का केस दर्ज

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर मीरगंज थाना अंतर्गत पुलिस ने विवाहित महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा उसे आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोप में वर्तमान में केराकत तहसील में तैनात नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के विरुद्ध शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।इस संबंध में शनिवार को जानकारी लेने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मीरगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी पुत्री श्वेता सिंह का विवाह वर्ष 2014 में बरसठी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुआ था और उसकी एक 10 वर्षीय पुत्री भी है। तहरीर में कहा गया है कि सुलतानपुर जिले के अमहट कोतवाली क्षेत्र के गोरा बारीक गांव निवासी विवेक श्रीवास्तव, जो वर्तमान में केराकत तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं, का उनके घर आना–जाना था। मछलीशहर तहसील में तैनाती के दौरान उन्होंने श्वेता सिंह से निकटता बढ़ाई और शादी का झांसा देकर अपने साथ रखने लगे। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपित ने पीड़िता का मानसिक उत्पीड़न किया, पर्यटन स्थलों पर ले जाकर अश्लील वीडियो बनाए तथा अन्य अधिकारियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डाला। इन परिस्थितियों से परेशान होकर श्वेता सिंह ने 9 मार्च को फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

मृतका की मां की तहरीर के आधार पर मीरगंज थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार की प्रतिमा स्थापना की मांग, प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री गिरीश चंद्र यादव को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव से शनिवार को जनपद के प्रजापति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट कर संविधान सभा के सदस्य एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार की प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग की। राहुल प्रजापति (जिला अध्यक्ष) के नेतृत्व में तथा दक्ष सेना के संस्थापक एवं प्रमुख वीरेंद्र प्रजापति वीर के साथ पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को प्रार्थना–पत्र सौंपते हुए कहा कि स्वतंत्रता

आंदोलन और संविधान निर्माण में रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार के योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी प्रतिमा स्थापित कराई जाए। इस पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रतिमा स्थापना के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में पवन प्रजापति, धर्मेंद्र प्रजापति, मोहन लाल प्रजापति, सुशील प्रजापति, लोटन प्रजापति, उमाशंकर प्रजापति, अभिषेक प्रजापति, मोनू प्रजापति सहित प्रजापति समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

सांप को बचाने के प्रयास में बाइक फिसली, सीएचसी के असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की मौत

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए सड़क हादसे में बरसठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में तैनात असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर दीपक कुमार सरोज (27) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से स्वास्थ्य विभाग और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। दीपक कुमार सरोज मूल रूप से वाजिदपुर गांव के निवासी थे। शनिवार को वह बाइक से किसी कार्य से जा रहे थे। गहरौल गांव के पास सड़क पार कर रहे एक सांप को बचाने के प्रयास में उन्होंने बाइक का संतुलन खो दिया। इसी दौरान सड़क निर्माण कार्य के लिए बिखरी गिट्टियों और पत्थरों पर बाइक फिसल गई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी शोक व्याप्त है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के बाद काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने तथा सड़क पर फैली गिट्टियों और पत्थरों को तत्काल हटाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।

तीसरी बार नरेंद्र मोदी विचार मंच के जिलाध्यक्ष बने संदीप श्रीवास्तव, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। नरेंद्र मोदी विचार मंच के शीर्ष नेतृत्व ने संदीप श्रीवास्तव पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताते हुए उन्हें जौनपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी पुनर्नियुक्ति की घोषणा के बाद संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है। जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर संदीप श्रीवास्तव ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सोनी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व द्वारा दोबारा जताया गया विश्वास उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने संगठन की विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर मेहनत की है। उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों, महिला शक्ति, युवा कार्यकर्ताओं और सभी सहयोगियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सहयोग और विश्वास के कारण ही उन्हें लगातार तीसरी बार यह दायित्व मिला है। संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले समय में संगठन के माध्यम से सामाजिक समरसता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवा जागरूकता, गरीब एवं जरूरतमंदों की सहायता तथा जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ष्सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयासष के संकल्प को जन–जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की एकता, अनुशासन और सेवा भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। पुनर्नियुक्ति पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संदीप श्रीवास्तव को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी विचार मंच, जौनपुर संगठनात्मक रूप से और अधिक सशक्त होगा तथा समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा।

समाजवादी पार्टी जौनपुर की मासिक बैठक संपन्न,संगठन को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी की शनिवार को जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष राकेश मौर्या की अध्यक्षता में मासिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने पर बल दिया। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा जनता के बीच पार्टी की नीतियों एवं उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजनारायण बिंद, पूर्व विधायक लालबहादुर यादव, पूर्व प्रत्याशी संजय सरोज, प्रदेश सचिव हिसामुद्दीन शाह, दीपचंद राम, कलीम अहमद, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश अहीर, जिला उपाध्यक्ष श्यामबहादुर पाल, हीरालाल विश्वकर्मा, महेंद्र प्रताप यादव, नेपाल राजेंद्र यादव श्टाइगरश, राजेंद्र यादव, उमाशंकर पाल, इरशाद मंसूरी, सुशील श्रीवास्तव, डॉ. वीरेंद्र यादव, लाल मोहम्मद रैनी, पूर्व प्रमुख रमापति यादव, कैलाशनाथ यादव, अजय त्रिपाठी मालती निषाद, हरिश्चंद्र प्रभाकर, राम अभिलाष यादव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रामजतन यादव, नंदलाल यादव, निजामुद्दीन अंसारी, राम अकबाल यादव, रामू मौर्य, लक्ष्मीशंकर यादव और रवि यादव सहित अनेक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया। इस दौरान मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र के नद्दीरामपुर निवासी अशोक मिश्रा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य एवं उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके जुड़ने से संगठन को और मजबूती मिलेगी। बैठक के समापन पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश सचिव ऊषा जायसवाल के पिता बसंतलाल गुप्ता एवं जनपद के अन्य पीडीए परिवारों में हुए दुखद निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई।

संत रविदास के समानता और समरसता के संदेश से ही सशक्त भारत का निर्माण – सीमा द्विवेदी

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर द्वारा महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत शनिवार को जिला कार्यालय पर श्री गुरु रविदास महाराज कलश वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) की पवित्र माटी से भरे कलश का विधि–विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने सामाजिक समरसता, समानता और बंधुत्व बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि संत रविदास जी ने ऊंच–नीच, जाति–पाति और भेदभाव से मुक्त समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उनका समानता और समरसता का संदेश आज भी राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार संत रविदास जी के सामाजिक न्याय और समरस समाज के सपने को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्य वक्ता एवं भाजपा जिला महामंत्री पीयूष गुप्ता ने कहा कि संत रविदास जी का जीवन भेदभाव रहित समाज की नींव है। उनका 650वां प्रकाश पर्व पूरे देश में ऐतिहासिक रूप से मनाया जा रहा है। कलश वंदन अभियान जिले के प्रत्येक मंडल और गांव तक पहुंचाकर सामाजिक समरसता का संदेश जन–जन तक पहुंचाया जाएगा। जिला महामंत्री अजय सिंह ने कहा कि सीर गोवर्धनपुर से आई पवित्र माटी सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक है। वहीं, जिला महामंत्री संदीप तिवारी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से संत रविदास जी के विचारों को घर–घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं -जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय–सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। जिन परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब हो रहा है, उनमें तेजी लाते हुए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मापुर के पुनर्निर्माण कार्य का गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए। त्रिलोचन महादेव मंदिर के दिव्य एवं भव्य रूप देने के लिए जिलाधिकारी स्तर से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए। साथ ही रासमंडल स्थित हनुमान जी मंदिर के सौन्दर्यीकरण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने एवं परिसर में फिनिशिंग कार्य और ग्रीनरी विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिला शौचालय एवं स्विमिंग पूल की क्रियाशीलता रखने के निर्देश दिए। जिला क्रीड़ा अधिकारी को स्टेडियम का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने साइबर थाना भवन का गुणवत्ता परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के अधिकारियों की बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध उच्च स्तर पर पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। शीतला चौकियां मंदिर से कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि श्रमिक बढाकर शीघ्र अति शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए तथा विभाग की सभी परियोजनाओं की अलग से विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने की बात कही। साथ ही सभी विभागों को नियमित स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पूर्ण परियोजनाओं को जनहित में शीघ्र संचालित कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया,जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डा0 अरूण कुमार यादव संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

साधु-संतों के वेश में संसद के बाहर प्रदर्शन पर भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने भेजा विधिक नोटिस

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।संसद भवन के समक्ष राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर साधु–संतों का वेश धारण कर किए गए राजनीतिक प्रदर्शन के विरुद्ध अब कानूनी मोर्चा खुल गया है।इस मौके पर भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव तथा सांसद अवधेश प्रसाद को विस्तृत विधिक नोटिस एवं सार्वजनिक आपत्ति–पत्र भेजते हुए आरोप लगाया है कि इस कृत्य से सनातन धर्म, साधु–संत परंपरा और करोड़ों रामभक्तों की धार्मिक भावनाओं का गंभीर अपमान हुआ है।विधिक नोटिस में कहा गया है कि साधु–संतों का स्वरूप भारतीय संस्कृति में तप, त्याग, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का सर्वोच्च प्रतीक है।ऐसे पवित्र स्वरूप का राजनीतिक प्रदर्शन, प्रचार अथवा आरोप–प्रत्यारोप का माध्यम बनाना धार्मिक आस्था के साथ अस्वीकार्य खिलवाड़ है। नोटिस में इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रतिकूल बताया गया है।नोटिस के माध्यम से राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद से बिना शर्त सार्वजनिक माफी, अपने कृत्य पर स्पष्ट खेद व्यक्त करने तथा भविष्य में धार्मिक वेशभूषा और संत परंपरा का राजनीतिक उपयोग न करने का लिखित आश्वासन देने की मांग की गई है।डॉ. रजनीश सिंह ने कहा,ष्अयोध्या किसी व्यक्ति, परिवार, राजनीतिक दल या संगठन की बपौती नहीं है। अयोध्या प्रभु श्रीराम की पावन नगरी है और इसकी मर्यादा पर आघात करोड़ों रामभक्तों की आस्था पर आघात है। लोकतंत्र के नाम पर संतों की पवित्र परंपरा का राजनीतिक उपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।ष्उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन धर्म, संत परंपरा और आस्था को राजनीतिक हथियार बनाना देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ अन्याय है। जो भी व्यक्ति धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग कर समाज को भड़काने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध कानून के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक और संवैधानिक उपाय अपनाए जाएंगे।विधिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मानहानि, क्षतिपूर्ति तथा अन्य उपलब्ध कानूनी कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी।डॉ. रजनीश सिंह ने कहा कि ष्सनातन परंपरा, साधु–संतों की गरिमा और प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या का सम्मान किसी राजनीतिक एजेंडे से ऊपर है।इसकी गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को कानून के दायरे में जवाब देना होगा।आस्था का अपमान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।ष

रोटरी क्लब ग्रेटर फैजाबाद का द्वादश पद ग्रहण समारोह संपन्न

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। रोटरी क्लब ग्रेटर फैजाबाद का द्वादश पद ग्रहण समारोह अमानीगंज स्थित होटल क्रिनोस्को में संपन्न हुआ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश रविकांत रस्तोगी उपस्थित रहें।कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलन के साथ प्रारम्भ हुआ।कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि का स्वागत क्लब के पूर्व अध्यक्ष अमित अग्रवाल द्वारा किया गया साथ में आयी हुईं उनकी धर्मपत्नी का स्वागत रोटरी क्लब ग्रेटर विंग की अध्यक्षा नीता मित्तल द्वारा किया गया।कार्यक्रम में सुनील रस्तोगी ने अध्यक्ष, सतीश चौरसिया ने सचिव, मुकेश अग्रवाल ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ली।क्लब के सचिव सतीश ने गत वर्ष क्लब द्वारा किये गए कार्यों की जानकारी दीं। निवर्तमान अध्यक्ष संजीव सोनी ने उत्कृष्ट कार्यों हेतु संजय मित्तल,अमित अग्रवाल, अखिलेश, नितेश, अनुराग अग्रवाल, देवेश, हिमांशु कंसल, ललित बंसल, नीरज सिंघल, अरुण अग्रवाल, पीयूष सिंघल,अतुल अग्रवाल, राहुल केसरवानी, सुनील रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रितेश गोयल, सतीश चौरसिया,डॉ मनीष अग्रवाल,नमन रस्तोगी, सपना रस्तोगी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। नव निर्वाचित सुनील रस्तोगी ने अपने उद्बोधन में क्लब द्वारा किए जा रहें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा कार्यों की विशेष प्रशंसा की और नई टीम से जनहित में और अधिक प्रभावी परियोजनाएं संचालित करने का आवाहन किया।क्लब के संस्थापक अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने कहा की रोटरी केवल सेवा का संगठन नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त माध्यम हैं द्य क्लब में एक नये मेंबर के रूप में अमित रस्तोगी ने भी शपथ ली द्य मुख्य अतिथि न्यायाधीश श्री रविकांत रस्तोगी जी ने अपने सम्बोधन में अध्यक्ष सुनील रस्तोगी एवं उनकी टीम को बधाई दीं और क्लब द्वारा किये जा रहें सामाजिक कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की एवं क्लब के उज्जवल भविष्य की कामना की।इस अवसर पर रोटरी क्लब ग्रेटर विंग की निवर्तमान चेयरपर्सन सपना रस्तोगी ने नवनिर्वाचित चेयरपर्सन नीता मित्तल को कार्यभार सौंपा और बधाई दीं।इस अवसर पर रस्तोगी समाज के अध्यक्ष प्रवीन रस्तोगी भी अपनी पत्नी के साथ उपस्थित रहें।कार्यक्रम का संचालन पीयूष सिंघल द्वारा किया गया।कार्यक्रम में अभिषेक अग्रवाल, जय आहूजा, अनुराग वैश्य, विकेश अग्रवाल, ऐश्वर्या रस्तोगी, प्रतीक रस्तोगी, दीपक मेहरोत्रा, अरुण साकेत, संजय अग्रवाल,दिनेश सिंह,अरविन्द अग्रवाल, आलोक सोनी,अखिल अग्रवाल, अभिषेक सिंघल, अमित सिंघल,रूमी रस्तोगी,स्वाति अग्रवाल,रश्मि केसरवानी,कलावती चौरसिया,सोनल रस्तोगी, दीपिका अग्रवाल,शिखा रस्तोगी,रश्मि अग्रवाल, मोना रस्तोगी,शिल्पी अग्रवाल,वंदना अग्रवाल,छवि अग्रवाल,सोनी रस्तोगी, अंशिका अग्रवाल,स्नेहा सिंघल,ज्योति रस्तोगी,रोलीदीप,सवी आनंद,पूजा रस्तोगी,श्रद्धा आदि उपस्थित रहीं द्य

हाईवे पर लूट और बाइक चोरी में शामिल आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले की रुदौली पुलिस ने हाईवे पर लूट और बाइक चोरी करने वाले दो शातिर अंतरजनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया।पुलिस ने गिरफ्तार किये गए आरोपियों की पहचान बबलू रावत (कोइलावर मांझा, दरियाबाद, बाराबंकी)और राकेश रावत (भुडेहरी, रामसनेही घाट, बाराबंकी) के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने 14 मई 2026 को कूढ़ा सादात पेट्रोल पंप के पास बस चालक से आईफोन–15, चांदी की दो अंगूठियां, एक चांदी का ब्रेसलेट और घ्6,000 लूटे थे।इसके अलावा 21 जून 2026 की रात हाईवे किनारे खड़ी अपाचे बाइक चोरी करने की घटना का भी पुलिस ने खुलासा किया।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 मोबाइल फोन (एक आईफोन सहित), घ्1,370 नकद और चोरी की अपाचे बाइक बरामद हुई। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किये गए बबलू रावत पर बाराबंकी और अयोध्या में लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट समेत 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।राकेश रावत पर डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 9 मुकदमे दर्ज हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने किया संगठन की समीक्षा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।शनिवार को सिराथू सपा विधायक पल्लवी पटेल अयोध्या पहुंचीं।इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने व दिनों मे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए संगठन की समीक्षा की जा रही है।उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी सक्रियता और संगठन की स्थिति का आकलन किया जाएगा।कहा कि जहां संगठन में घ्नट–बोल्ट ढीलेष्ठ हैं, उन्हें समय रहते ष्ठीकष्ठ किया जाएगा।उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारी को लेकर जमीनी स्तर पर लगातार संवाद जरूरी है।संसद के बाहर सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर भी उन्होंने कहा कि संसद देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है,जहां हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चढ़ावे की चोरी का मामला नहीं है।उनके अनुसार आम जनता के अधिकारों और नौकरियों की भी घ्चोरीष्ठ हो रही है,जिन पर भी संसद में चर्चा आवश्यक है।पल्लवी पटेल ने कहा कि जनता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में गंभीरता से उठाया जाना चाहिए।

डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिसर मे वृक्षारोपण का हुआ आयोजन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय मे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लीला हरि फाउंडेशन के तत्वाधान में विश्वविद्यालय के कैंपस में कलार्थ जीवंत वाटिका, मे वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी की पत्नी राजलक्ष्मी त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन डॉक्टर आरपी सिंह,, अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह थे।डॉ विजेंद्र सिंह जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के निर्देशन में विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण के विभिन्न आयोजन किया जा रहे हैं, आने वाले समय में विश्वविद्यालय में एक सुंदर तालाब वह वाटिका का भी निर्माण किया जाएगा,आज मे लीला हारी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं जिनके तत्वाधान में, वृक्षारोपण का आयोजन किया गया,, हम सभी की यह पहल होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाया जाए, मैं अयोध्या के सभी जनपद वासियों से भी निवेदन करता हूं कि वह अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर अपने प्रदेश अपने देश को हरा–भरा बनाए।मुख्य अतिथि राजलक्ष्मी ने बताया कि वृक्ष लगाने से हमारा वातावरण शुद्ध व सुंदर रहता है।ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए जिससे जीव जंतु पक्षी सभी, सुंदर माहौल में जीवन व्यतीत करते हैं ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने से जब वातावरण शुद्ध रहेगा तो, जनमानस रोग मुक्त रहेगा।परिवहन विभाग के ए.आर.टी.ओ डीआर आरपी सिंह ने कहा कि आज के समय में रोड पर इतने यातायात इतना प्रदूषण हो गया है इससे लड़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर, ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है।रोड के किनारे वृक्ष लगाना चाहिए खुले मैदान में वृक्ष लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए पीपल का वृक्ष लगाए नीम का वृक्ष लगाए, जिससे वातावरण शुद्ध रहे और वातावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उससे लड़ने के लिए मानव शरीर को एक ताजी हवा और शुद्धता प्राप्त हो सके।लीला हारी फाउंडेशन की, कुमारी निहारिका श्रीवास्तव ने बताया कि आज वृक्षारोपण का आयोजन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कैंपस में, किया गया।इस मौके पर उन् मुख्य उद्देश्य है की ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए और अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए रोग मुक्त करने के लिए, वृक्ष लगाने की आवश्यकता बहुत है आज देखा जा सकता है कि जीव जंतु यहां तक की विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजातियों की जो पंछी थे वह लुप्त होते जा रहे हैं, जीव जंतु और पंछी को बचाने के लिए हमें जल की व्यवस्थाव वृक्ष को लगाना बहुत जरूरी है आज हम सभी लोगों ने विश्वविद्यालय के इस कैंपस में 35 पेड़ लगाए और यह अभियान हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे,,

विश्वविद्यालय के डॉ विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि आज के इस आयोजन के लिए हम लीला हारी फाउंडेशन को बहुत–बहुत बधाई देते हैं और यह पूरा आयोजन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कुलपति महोदय के निर्देश पर किया गया, आज जिस प्रकार से वातावरण दूषित होता जा रहा है उसके बचाव के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए,, वृक्ष लगाने की आवश्यकता,, तालाब व शुद्ध जल की आवश्यकता, बहुत अधिक है और इस परिपेक्ष में आज हम सभी ने यहां पर वृक्षारोपण किया।

प्रधानाचार्य परिषद की नई कार्यकारिणी गठित, रामप्रिया जिला अध्यक्ष और डॉ.रमेश बने जिला मंत्री

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की नई कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से हिंदू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम प्रिया शरण सिंह को जिलाध्यक्ष व राष्ट्रीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज पिठला के प्रधानाचार्य डॉ. रमेश कुमार मिश्रा को जिला मंत्री चुना गया।यह निर्णय शनिवार को शहर के मेथाडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित परिषद की आमसभा बैठक में लिया गया।कार्यकारिणी में संरक्षक पद पर प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एसएसवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मणि शंकर तिवारी जबकि जिला कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में द्वापर विद्यापीठ इंटर कॉलेज बरईपारा मया के प्रधानाचार्य सुनील कुमार द्विवेदी को मनोनीत किया गया है। एमएलएमएल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. उदय भान सिंह जिला कोषाध्यक्ष और साहबदीन सीताराम स्कूल की प्रधानाचार्या ममता निषाद आय– व्यय निरीक्षक के पद का दायित्व संभालेंगे।इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी में तीन महिला उपाध्यक्ष सहित दस उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर जिले के कई विद्यालय के प्रधानाचार्य निर्वाचित घोषित किए गए।प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मणि शंकर तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई।मंत्री राम प्रिया शरण सिंह ने पिछली कार्यवाही सभी के समक्ष रखी।जिसका सदन ने सर्वसम्मत से अनुमोदन कर दिया।इसके बाद प्रधानाचार्य की समस्याओं और उसके निदान पर विस्तार से चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि यदि शिक्षा अधिकारियों द्वारा समस्याओं का सम्यक निस्तारण नहीं किया गया तो परिषद आंदोलन को बाध्य होगा। प्रधानाचार्य परिषद जल्द ही प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें भी समस्याओं से अवगत कराएगा।परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मणि शंकर तिवारी और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ. वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सभी तदर्थ प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण और विनियमितीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।डॉ.तिवारी ने इस संबंध में परिषद की ओर से किए जा रहे क्रियान्वयन के बारे में भी बताया। जिस पर सदन ने सकारात्मक निर्णय लिया और सुझाव साझा किए।प्रधानाचार्य परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाई का भी सुझाव सामने आया।आम सभा ने निर्णय लिया की सदस्यता बढ़ाने के लिए परिषद की ओर से अभियान चलाया जाएगा।आम सभा बैठक का संचालन मंत्री राम प्रिया शरण सिंह ने किया बैठक में परिषद के संरक्षक डॉ.राम सुरेश मिश्रा, डॉ. शिव कुमार मिश्रा सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

निर्माणाधीन पुलिया पर बैरियर तोड़कर बाइक टकराई, अधेड़ की मौत

ब्यूरो चीफ . आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, बालमुकुंद पांडे (45) पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण पांडे निवासी ग्राम भवानीपुर सरैया, थाना मोतीगरपुर, अपनी हीरो मोटरसाइकिल से बिरसिंहपुर रोड से बगिया चौराहे की ओर जा रहे थे। रास्ते में सपाही के पास निर्माणाधीन पुलिया पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरियर को बाइक ने तोड़ दिया, जिसके बाद वाहन पुलिया के स्लैब से टकरा गया। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पीआरवी के माध्यम से पुलिस को मिली। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को 100 शैया अस्पताल, बिरसिंहपुर भिजवाया, जहां पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए गए हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद यातायात सामान्य रहा तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। मामले में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर सुनील कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रही है।

कुएं में मिला अधेड़ का शव, इलाके में सनसनी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित केराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव के रग्घूपुर पुरवा में शनिवार को एक कुएं से अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान राकेश शुक्ला (45) पुत्र मानिक शुक्ला के रूप में हुई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं।इस मामले में जानकारी लेने पर क्षेत्राधिकारी केराकत अजय कुमार कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

जिलाधिकारी एवं रेडक्रॉस अध्यक्ष की मानवीय पहल का इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी ने किया स्वागत

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव' 'शाहजहांपुर' मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय प्रांगण स्थित इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में सचिव डॉ

विजय जौहरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनपद के जिलाधिकारी एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, के अध्यक्ष धर्मेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अल्ट्रा

'जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव' 'हरदोई' शनिवार को तहसील सदर में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के दौरान बड़ी संख्या में आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।

राजस्व टीम पर हमले के विरोध में तहसील में धरना, आरोपितों की गिरफ्तारी व एसएचओ के स्थानांतरण की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव में पैमाइश के दौरान राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व टीम पर हुए कथित हमले के विरोध में शनिवार को तहसील परिसर में राजस्व कर्मियों ने धरना–प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मछलीशहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) के स्थानांतरण की मांग उठाई। धरनारत राजस्व कर्मियों ने उपजिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि घटना में शामिल अराजक तत्वों के विरुद्ध पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि आरोपितों को संरक्षण मिलने से राजस्व कर्मियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। राजस्व कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना एवं कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष जगवीर गौतम ने की, जबकि संचालन महामंत्री आशीष पटेल ने किया। वक्ताओं ने राजस्व कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। धरने में पूर्व खंड मंत्री लालचंद्र यादव, प्रदेश महामंत्री राहुल पटेल, जयशंकर यादव, जयप्रकाश शर्मा, दुर्जन प्रसाद, प्रिया मौर्या, चंद्रावती, अजीत कुमार पांडेय सहित बड़ी संख्या में राजस्व कर्मी उपस्थित रहे।

सेवानिवृत कर्मियों को डीआईजी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

अयोध्या।डीआईजी कार्यालय मे तैनात मुख्य आरक्षी डा0ओमप्रकाश सिंह एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंगदराम के सेवानिवृत होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया।इस मौके पर डीआईजी सोमेन बर्मा ने कार्यालय में तैनात मु0आ0 डा0ओम प्रकाश सिंह एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंगदराम के सेवानिवृत्ति के अवसर पर दोनों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र,स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया।साथ ही साथ सेवानिवृत हुए दोनों कर्मियों के उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए कर्तव्य निष्ठा की सराहना की गयी।इस अवसर पर निरीक्षक अरविन्द सिंह,निरीक्षक लेखा सुरेश कुमार मौर्य,गोपनीय सहायक नवीन सिंह, उपनिरीक्षक देवेश त्रिपाठी, उपनिरीक्षक श्रीप्रकाश पाण्डेय, उपनिरीक्षक विजय पाण्डेय, उपनिरीक्षक राकेश मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार

अयोध्या कोतवाली नगर पुलिस में चोरी में वांछित आरोपी को चोरी के समान के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि चौकी प्रभारी फतेहगंज विकास गुप्ता ने शनिवार को आरोपी आकाश यादव पुत्र स्व0 गिरधारी लाल यादव को मर्चरी हाउस के सामने के पास से गिरफ्तार किया।बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपों के पास चोरी के कई सामान बरामद किए गए। बताया कि उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में प्रभारी निरीक्षक चौकी फतेहगंज विकास गुप्ता के अलावा चौकी प्रभारी नवीन मंडी संजय कुमार यादव, उप निरीक्षक चंद्रशेखर यादव,अखिलेश तिवारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों की भूमिका रही।

मुख्य आरोपी के पिता, भाई और दो भाभियां भी जेल भेजी गईं

गोरखपुर, (संवाददाता)। सर्राफा कारोबारी हनुमान वर्मा के 10 वर्षीय बेटे वैभव वर्मा के अपहरण और हत्या के मामले में खजनी पुलिस ने मुख्य आरोपी सर्वेश उर्फ बिट्टू शर्मा के परिवार के चार अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर चारों की भूमिका अपहरण और हत्या की साजिश में सहयोग करने की सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी सर्वेश उर्फ बिट्टू शर्मा के पिता हरिनारायण शर्मा, बड़े भाई सत्येंद्र कुमार भट्ट उर्फ जिले, पत्नी अनामिका शर्मा और भाई सतीश शर्मा की पत्नी बबली शर्मा शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका मुख्य आरोपी की मदद करने और अपराध की साजिश में सहयोग करने के रूप में सामने आई है। खजनी थानाध्यक्ष जयंत कुमार सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना अभी जारी है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।